भोपाल, शनिवार
19
अप्रैल-2025

दैनिक
पीपुल्स प्रवक्ता

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

/Peoplespravakta

E-paper www.peoplespravakta.com | वर्ष: 09 | अंक : 05 | पृष्ठ : 08 | मूल्य : 02 रुपए | E-mail Peoplespravakta@gmail.com

सुविचार

धैर्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है।

पृथ्वी पर निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा, अन्न और जल को सुरक्षित रखना होगा : केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

वन प्रबंधन में औपनिवेशिक सोच से मुक्त होना जरूरी : मुख्यमंत्री

- वन क्षेत्र में विद्यमान जनजातीय समुदाय के आस्था स्थलों का होगा संरक्षण
- नदियों का प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रदेश के वनों का संरक्षण आवश्यक
- मुख्यमंत्री ने जताई प्रवासी पक्षियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और रैप्टाईल्स व जल जीवों के संरक्षण के लिए कार्य योजना की आवश्यकता
- जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वन, आजीविका से सम्बद्ध विषय है। जनजातीय क्षेत्र में अपार वन संपदा उपलब्ध है। इसके प्रबंधन में ध्यान रखना होगा कि विकास से जनजातीय वर्ग के हित प्रभावित न हो। भारतीय जीवन पद्धति वनों पर आधारित रही है। वनों के प्रबंधन में औपनिवेशिक सोच से मुक्त होने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विरासत से विकास और प्रकृति को जोड़ते हुए प्रगति और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित कर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। पेसा एक्ट इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीवन का आनंद समग्रता में है, और प्रकृति आधारित जीवन जीने से कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव जनजातीय क्षेत्रों में वन पुनर्स्थापना, जलवायु परिवर्तन और समुदाय आधारित आजीविका पर प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव तथा केन्द्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर तथा भगवान बिरसा मुंडा और वीरांगना रानी दुर्गावती के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। प्रदेश के महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया, केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उईके भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में वनों की स्थिति में सुधार और वन प्रबंधन में नवाचार के लिए वन विभाग को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण से इको सिस्टम बेहतर हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर चीतों का पुनर्स्थापना हो पाया है। उन्होंने किंग कोबरा सहित रैप्टाइल्स की प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता जताते हुए कहा कि इससे सर्पदंश की घटनाओं में कमी आएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन क्षेत्र में विद्यमान जनजातीय समुदाय के पूजा और आस्था स्थलों के संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। आवश्यकता होने पर केंद्र शासन से भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वन की दृष्टि से बहुत संपन्न है। प्रदेश में यद्यपि कोई ग्लेशियर नहीं है, किन्तु प्राकृतिक रूप से वनों से निकलने वाली जल राशि से ही प्रदेश से निकलने वाली बड़ी नदियां आकार लेती हैं। मध्यप्रदेश से निकली सोन, केन, बेतवा, नर्मदा नदियां देश के कई राज्यों में जल से जीवन पहुंचा रही हैं। बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश की प्रगति में प्रदेश के वनों से निकले इस जल का महत्वपूर्ण योगदान है। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश के वन, पूरे देश के वन हैं। इन नदियों के संरक्षण और उनके निर्मल अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए मध्यप्रदेश के वनों का संरक्षण और संवर्धन महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा समग्र के माध्यम से नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। अन्य नदियों पर भी कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल (पीकेसी) लिंक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार माना। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से प्रदेश के बड़े क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता और सिंचाई सुविधा सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल जीवों के संरक्षण पर कार्य करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ने वन्य प्राणियों के संरक्षण में विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने प्रवासी पक्षियों पर केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन संरक्षण के साथ-साथ आजीविका को सरल और सुलभ बनाने के लिए आयोजित कार्यशाला की सफलता की कामना करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के साथ-साथ वन-पर्यावरण के संरक्षण में भी यह कार्यशाला उपयोगी सिद्ध होगी।

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री यादव ने कहा कि हमें प्रकृति के संरक्षण के लिए समुदाय आधारित योजनाएं तैयार करने की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रकृति के संरक्षण के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ पर ध्यान देने के लिए जनता को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। पृथ्वी पर निवासरत प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा, अन्न और जल को सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरण संरक्षण में सॉलिड वेस्ट और ई-वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी चुनौती हैं। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना आवश्यक है।

केन्द्रीय मंत्री श्री यादव ने कहा कि विकास की इस धारा में वन और प्रकृति के संरक्षण को साथ लेकर चलना होगा। केंद्र सरकार ने कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से वनों में रहने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन के लिए कार्य किया है। वन और यहां रहने वाले लोगों के विकास और संरक्षण के लिए समग्र चिंतन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य हो रहे हैं। एक पेड़ मां के नाम हमारा बड़ा अभियान बन चुका है। नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सोलर एनर्जी अलायंस बनाया गया है। प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भी अलायंस की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बायोफ्यूल अलायंस बनाया गया है। भारत आज दुनिया के विकासशील देशों में ग्लोबल साऊथ का नेतृत्व कर रहा है। हमें वोकल फॉर लोकल तो होना है, साथ में भारत को जनजातीय वर्ग और पर्यावरण के संरक्षण में वैश्विक नेतृत्वकर्ता भी बनना है।

केन्द्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय समाज और वनों का संबंध अभिन्न है। मिश्रित वनों के शरण के कारण जनजातीय समुदाय वन क्षेत्र से पलायन के लिए विवश हो रहा है। इसी का परिणाम है कि वन प्रबंधन और जनजातीय समुदाय के आजीविका के संसाधनों पर विचार-विमर्श की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। भारत में अरण्यक संस्कृति में ही वेद पुराण आदि का लेखन संपन्न हुआ। भारतीय ज्ञान परंपरा और वन्य व जनजातीय समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं।

पूर्व आंध्र सीएम जगन के 27.5 करोड़ के शेयर जब्त

डालमिया सीमेंट की 793 करोड़ की जमीन भी अटैच

पीपुल्स प्रवक्ता, हैदराबाद।

रेड्डी पर यह कार्रवाई 14 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के एक पुराने मामले में की गई है। जिसमें 'क्विड प्रो क्वो' (कुछ पाने के बदले कुछ देना) निवेश होने के आरोप हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 27.5 करोड़ रुपए के शेयर अस्थायी रूप से जब्त किए हैं। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के 14 साल पुराने मामले में की गई है। जिसमें 'क्विड प्रो क्वो' (कुछ पाने के बदले कुछ देना) निवेश होने के आरोप हैं।

ED की हैदराबाद टीम ने जगन की तीन कंपनियों – कार्मेल एशिया होल्डिंग्स, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में निवेश को जब्त किया है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की करीब 377.2 करोड़ रुपए की जमीन भी जब्त की गई है। DCBL के मुताबिक, यह जमीन 793.3 करोड़ रुपए की है। यह मामला 2011 में CBI द्वारा दर्ज किए गए केस से जुड़ा है, जिसमें आरोप है कि DCBL ने रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड (जगन रेड्डी से जुड़ी कंपनी) में 95 करोड़ रुपए निवेश किए थे। इसके बदले में जगन ने अपने पिता, तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के प्रभाव का इस्तेमाल कर DCBL को आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 407 हेक्टेयर की खनन लीज दिलाई थी।

अब आंध्र में भी एससी आरक्षण में सब-कोटा

अध्यादेश जारी ; सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उठाया कदम

अमरावती, एजेंसी

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 15 अप्रैल को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। आंध्र प्रदेश ने गुरुवार को अनुसूचित जातियों आरक्षण के भीतर आरक्षण देने के लिए अध्यादेश जारी किया। राज्य में कुल 59 SC जातियों को 15 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को SC और अनुसूचित जनजातियों कोटे में कोटा देने की अनुमति दी थी। आंध्र प्रदेश के अध्यादेश में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए SC जातियों को तीन ग्रुप में बांटा गया है। इसमें चंदाला, पाकी, रेल्ली, डोम जैसी 12 जातियों को 1% आरक्षण के साथ ग्रुप-I, चमार, मादिगा, सिंधोला, मातंगी जैसी जातियों को 6.5त्न आरक्षण के साथ ग्रुप-II में और माला, अदि आंध्र, पंचमा जैसी जातियों को 7.5त्न आरक्षण के साथ ग्रुप-III में रखा गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले साल दिसंबर में रिटायर्ट IAS राजीव रंजन मिश्रा को SC कोटे में कोटा देने के लिए एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया।

आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर रिपोर्ट दी थी, जिसे केंद्र को भेजा गया था। तेलंगाना और हरियाणा पहले ही लागू कर चुके कोटे में कोटा इससे पहले तेलंगाना और हरियाणा सरकार SC कोटे में कोटा लागू कर चुकी है। तेलंगाना ने 14 अप्रैल को आदेश जारी कर स्ष्ट जातियों को तीन ग्रुप में बांटा है।

अस्पताल में डिजिटल रेप केस, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट

पीपुल्स प्रवक्ता, गुरुग्राम।

गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में बंगाल की एयर होस्टेस से डिजिटल रेप केस में हरियाणा सरकार की एंट्री हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने गुरुग्राम सेहत विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर ली है। जिसके बाद एयर होस्टेस की मेडिकल कराने का फैसला किया गया है। गुरुग्राम की चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. अलका सिंह डॉक्टरों का बोर्ड बनाएंगी। सोमवार को पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा। इसके लिए डॉ. अलका सिंह ने मेदांता अस्पताल से इलाज की डिटेल मंगाई है। उन्होंने एडमिट होने से लेकर डिस्चार्ज तक की हिस्ट्री मांगी है। सोमवार को ही मंत्री आरती राव को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं, इस केस की जांच के लिए पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने गुरुवार शाम को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी। इसकी अगुआई DCP हेडक्वार्टर डॉ. अर्पित जैन करेंगे। वह खुद भी MBBS डॉक्टर हैं। टीम में ACP डॉक्टर कविता, ACP यशवंत, सदर थाने के SHO इंस्पेक्टर सुनील, महिला थाना ईस्ट इंचार्ज नेहा राठी और सेक्टर 40 के CIA इंचार्ज अमित को शामिल किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, पीड़िता ने FIR दर्ज कराई तो उसमें कुछ नई बातें बताई हैं। 46 वर्षीय एयर होस्टेस ने कहा है कि वह 6 अप्रैल की रात को वेंटिलेटर पर थी। इसी दौरान उसके साथ यह वारदात हुई।

गीता और नाट्यशास्त्र यूनेस्को की लिस्ट में हुए शामिल

नई दिल्ली। श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को UNESCO ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। इसके साथ ही, अब हमारे देश के 14 अभिलेख यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ङ्ग पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा- यह वैश्विक सम्मान भारत के शाश्वत ज्ञान और कलात्मक प्रतिभा का जश्न है। ये कालातीत रचनाएं साहित्यिक खजाने से कहीं अधिक हैं। ये दार्शनिक आधार हैं जिन्होंने हमारे सोचने, महसूस करने, जीने और अभिव्यक्त करने के तरीके को बेहतर बनाया है। 18 अप्रैल यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे के दिन इसे शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा- यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में गीता और नाट्यशास्त्र को शामिल करना हमारे शाश्वत ज्ञान और समृद्ध संस्कृति की वैश्विक मान्यता है। गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना का पोषण किया है। उनकी अंतर्दृष्टि दुनिया को प्रेरित करती रहती है।

वक्फ विधेयक असंवैधानिक हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा : जेपीसी अध्यक्ष

नई दिल्ली, एजेंसी।

वक्फ विधेयक के असंवैधानिक होने के सवाल पर BJP नेता और जाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि- अगर समिति की रिपोर्ट कानूनी रूप से गलत पाई जाती है तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने विपक्ष के धार्मिक भेदभाव फैलाने के दावों और वक्फ संपत्तियों और बोर्ड की सदस्यता के बारे में चिंताओं को नकारते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक निकाय नहीं है, बल्कि एक कार्यकारी निकाय है, एक वैधानिक निकाय है जो सिर्फ संपत्तियों की देखभाल करता है। वहीं, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर एक अहम निर्देश जारी किया। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले में सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई की जाएगी, जबकि बाकी करीब 65 याचिकाओं को हस्तक्षेप या पक्षकार याचिकाओं के रूप में जोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह फैसला अदालत में ज्यादा भीड़ और कार्यवाही के दौरान होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। कोर्ट ने यह भी बताया कि जिन 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, उन्हें खुद याचिकाकर्ताओं ने आपसी सहमति से नामित किया है, ताकि सभी की बात सामने रखी जा सके और सुनवाई व्यवस्थित ढंग से हो।

मुर्शिदाबाद हिंसा- राज्यपाल मालदा पहुंचे

पीड़ितों से मिलकर केंद्र को रिपोर्ट भेजेंगे विश्व हिंदू परिषद का आज देशभर में प्रदर्शन

नई दिल्ली, एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस शुक्रवार को मालदा पहुंचे हैं। इसके बाद ट्रेन से मुर्शिदाबाद जाएंगे। यहां अगले 2 दिन राज्यपाल हिंसा प्रभावित इलाकों और शरणार्थी शिविरों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा- मैं जमीनी स्थिति का जायजा लूंगा। वहां जो कुछ भी हुआ चौंकाने वाला है। किसी भी कीमत पर शांति स्थापित होनी चाहिए।

बोस ने कहा कि वह पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देंगे। इससे पहले गुरुवार को ष्टरूममता बनर्जी ने राज्यपाल से दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया था। ममता ने कहा- मैं

गैर-स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वे अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। उधर, विश्व हिंदू परिषद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है। वीएचपी कार्यकर्ता शनिवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेंगे। वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि देश भर के हर जिला मुख्यालय में जिलाधिकारियों को ज्ञापन देकर मांग करेंगे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने पर विचार करे।

17 अप्रैल : ममता सरकार ने हिंसा पर रिपोर्ट पेश की जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस राजा बसु चौधरी की बेंच नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई की केंद्र की ओर से पेश हुए वकील ने संवेदनशीलता को देखते हुए मुर्शिदाबाद में सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) की तैनाती बढ़ाने की मांग रखी। वहीं, ममता सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की। इसमें ममता सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में हैं। कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस और अन्य सभी पक्षों को चेतावनी दी कि कोई भी भड़काऊ बयानबाजी न करे। कोर्ट ने कहा, कृपया कोई भी भड़काऊ भाषण न दें।

शरबत जिहाद पर रामदेव बोले-

मैंने नाम नहीं लिया था रूह अफजा वालों ने खुद समझा

मथुरा, एजेंसी।

योग गुरू बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद को लेकर दिए अपने पुराने बयान का बचाव किया। रामदेव ने कहा- मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। रूह अफजा वालों ने इसे अपने ऊपर लिया। इसका मतलब वे जिहाद कर रहे होंगे। रामदेव बाबा शुक्रवार को मथुरा पहुंचे थें। उन्होंने आगे कहा कि, हमदर्द जैसी कंपनियां को लगता है कि वे पूरी तरह से इस्लाम को समर्पित हैं। और मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। यहां बात सनातनियों की है, उन्हें समझना चाहिए कि किससे सनातन का गौरव बढ़ रहा है और किससे इस्लाम का प्रचार हो रहा है। अब इसको लेकर भी किसी के पेट में दर्द होता है तो होने दो, ये शरबत जिहाद है तो है।

शरबत जिहाद' से जुड़ा पूरा मामला क्या है

योग गुरु रामदेव ने 3 अप्रैल को सोशल मीडिया X पर 10 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में रामदेव बाबा पतंजलि के शरबत का प्रचार करते दिख रहे हैं। वह कह रहे हैं- गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर है। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है। जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है, उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। अगर आप वो शरबत पिएंगे, तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे।